the basis of the results available to us, for pre-natal diagnosis; in certain cases, where a serious deformation was discovered, medical advice was given. Out of these 11,000 families, 1700 families were tribal families. We are on the job, with our limited resources i.e. just Rs. 5-6 crores. We are trying to do our best and I assure you that our main aim is to apply this research to Indian problems and to Indian conditions.

SHRI KAPIL SIBAL: Sir, apropos what the hon. Minister has said, I would like to put him one question. I believe that in the United States, *some* other scientists have already applied for patenting of the sequencing. If this is a fact, I would like *to* know from the hon. Minister whether he has taken up this issue in the Indo-US Forum?

DR. MURLI MANOHAR JOSHI: Well, as for the question as to how many scientists have applied for patents, I need a separate notice. But there has been no meeting of the Indo-US Scientific Forum as yet; as soon as the meeting takes place, we will discuss all these issues.

उत्तर प्रदेश में उर्वरक परियोजनाएं

*182.**श्री मनोहर कान्त ध्यानी**: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में स्थापित की गई उर्वरक परियोजनाओं और उनके वार्षिक उत्पादन तथा आय का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन एककों में से किसी एक एकक में विदेशी निवेश किया गया है; और

(ग) गोरखपुर उर्वरक परियोजना की स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री सुरेश प्रभू): (क) से (ग) एक विवरण-पत्र सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्र में स्थापित प्रमुख यूरिया उत्पादक उर्वरक एककों के ब्यौरे, उनकी वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता तथा वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान कर पूर्व लाभ का ब्यौरा विवरण-1 में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) जी, नहीं।

(ग) फर्टिलाइज़र कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एफ.सी.आई.) के गोरखपुर संयंत्र के प्रचालन कार्य 1990 से बन्द है। कृभकों ने गोरखपुर में एफ.सी.आई. के मौजूदा स्थल पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का उपयोग करके प्रतिवर्ष 7.68 लाख मीट्रिक टन क्षमता का नया यूरिया संयंत्र स्थापित करने में रूचि दर्शाई है। सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को पी.आई.बी. द्वारा निवेश मूल्यांकन की शर्त के अध्यधीन 'सिद्धान्ततः' अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इस परियोजना का निवेश मूल्यांकन पी.आई.बी. द्वारा दिनांक 9.7.99 को हुई इसकी बैठक में किया गया है। पी.आई.बी. के निष्कर्षों/अभ्युक्तियों के आधार पर, एक प्रस्ताव सरकार के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

विवरण-I

क्र०स०	कम्पनी/एकक का नाम	उत्पादन (000 मी० टन)			आय (कर पूर्व लाभ) (रुपये करोड़)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
	सार्वजनिक क्षेत्र						
1	एफ०सी०आई०: गोरखपुर	0.0	0.0	0.0	-102.08	-128.08	-150.00
	सहकारी क्षेत्र						
2	इफको: आवला	1672.1	1689.6	1578.6	127.07	152.67	152.24
3	इफको: फूलपुर	794.1	1404.4	1312.6	7.55	86.29	135.00
	निजी क्षेत्र						
4	डंकन इंडस्ट्री लि० कानपुर*	733.7	732.8	694.9	70.46	91.92	37.14
5	इन्डो-गल्फ कारपोरेशन लि०: जगदीशपुर*	933.8	1020.0	1042.0	157.86	183.50	239.81
6	टाटा केमिकल लि०: बबरोला	1021.0	878.4	982.3	156.18	116.93	27.56
7	ओसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र लि०: शाहजांहपुर*	930.0	890.7	871.7	100.10	32.37	67.60

*इन कम्पनियों के बारे में आय के आंकड़े बहु-उत्पाद प्रचालन के परिणाम दर्शाते हैं।

Fertilizer Projects in Uttar Pradesh

† *182. SHRI MANOHAR KANT DHYANI: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) The details of fertilizers projects established in Uttar Pradesh in public and private sectors, alongwith their annual production and income separately;

(b) whether foreign investment has been made in any of such units; and

(c) the status of Gorakhpur fertilizer project?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Details of major urea producing Fertilizer units established in Uttar Pradesh in Public, Cooperative and Private Sector, along with their annual production of urea and profit before tax for the period 1997-98 to 1999-2000 are given in Statement-I. *(See* below).

(b) No, Sir.

(c) The operation of the Gorakhpur Plant of Fertilizer Corporation of India Ltd. (FCI) have been suspended since 1990. KRIBHCO has evinced interest in setting up a new 7.68 lakh MT per annum urea plant at the existing site of FCI using the available infrastructure facilities at Gorakhpur. This proposal has been given 'in principle' approval by the Government subject to investment appraisal by **PIB.** The investment appraisal of this project was undertaken by PIB in its meeting held on 9.7.99. Based on the conclusions/observations of the PIB, a proposal has been submitted for Government's approval.

† Original notice of the question was received in Hindi.

Statement-I

SI. No.	Name of the Company/ Unit	Production (000' : MT)			Income (Profit before tax) (Rs. Crore)		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
	Public Sector:						
1.	FCI: Gorakhpur	0.0	0.0	0.0	-102.08	-128.98	-150.00
	Cooperative Sector:						
2.	IFFCO: Aonla	1672.1	1689.6	1578.6	127.07	152.67	152.24
3.	IFFCO: Phulpur	794.1	1404.4	1312.6	7.55	86.29	135.00
	Private Sector:						
4.	Duncans Industries Ltd.: Kanpur*	733.7	732.8	694.9	70.46	91.92	37.14
5.	Indo Gulf Corporation Ltd.: Jagdishpur*	933.8	1020.0	1042.0	157.68	183.50	239.81'
6.	Tata Chemcials Ltd.: Babrala	1021.0	878.4	982.3	156.18	116.93	27.56 (Prov.)
7.	Oswal Chemicals & Fertilizers Ltd.: Shahjahanpur*	930.0	890.7	871.7	100.10	32.37	67.60

* Income figure in respect of the these companies indicate results of multi production operations.

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: माननीय सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश के पूर्वाचल में जनसंख्या का भारी घनत्व है और उस क्षेत्र में लोग केवल कृषि पर आधारित हैं। किन्तु एकमात्र खाद का कारखाना जो गोरखपुर में स्थित है वह 1990 से बंद चल रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक तो वहां जो सरकारी क्षेत्र के कारखाने हैं उनका उत्पादन निरंतर घट रहा है, इसके क्या कारण हैं और सरकार उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्वाई कर रही है?

श्री सुरेश प्रभू: सर, खाद के कारखाने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही स्थित नहीं हैं लेकिन पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं और वे अपना प्रोडक्शन केपिसिटी के मुताबिक ही काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में इफको के दो कारखाने हैं। उनके प्रोडक्शन में तो हमने वृद्धि देखी है लेकिन यदि किसी खास कारखाने के बारे में जिक्र करें जहां प्रोडक्शन में कमी आ रही है तो उसके लिए खास वजह होगी। उसको हम देखकर ही जानकारी दे सकते हैं।

श्री मनोहर कान्त ध्यानी: सभापति महोदय, मंत्री जी ने अपने बयान में कहा है कि कृभकों द्वारा गोरखपुर के कारखाने का पुनरूद्धार किया जाएगा और 7.68 लाख प्रति टन की क्षमता से कार्य प्रारंभ किया जाएगा। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह परियोजना कब तक स्वीकृत हो जाएगी और कब तक यह काम करने लग जाएगा और इससे जनता को लाभ कब तक प्रारम्भ होने लग जाऐंगे?

श्री सुरेश प्रभू: गोरखपुर में जो कारखाना फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया के स्वामित्व में है उसको लेने की इंटेंशन कृभको ने सरकार के पास जाहिर की थी और उसके मुताबिक उन्होंने जो प्रोपोजल दिया था वह प्रोपोजल काफी एडवांस स्टेज में पहुंच गया है। लेकिन यह कारखाना फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया के स्वामित्व में है और उनकी हियरिंग बी०आई०एफ०आर० के सामने चल रही है। जब तक फार्मली बी०आई०एफ०आर० उसको यह आर्डर नहीं देती कि यह कारखाना बंद किया जाएगा तब तक फर्टिलाइज़र कार्पो० आफ इंडिया को यह कारखाना कृभकों को देने के लिए जो फार्मलटीज़ हैं वह कम्पलीट करने के बाद ही किया जाएगा।

श्री नरेन्द्र मोहन: सभापति महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उसमें कुछ बातें और आतीं तो अच्छा रहता। कारखानों की दशा के बारे में उन्होंने बताया है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कारखाने के बारे में, 1999-2000 में इस कारखाने में 150 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। अब तक कुल कितना घाटा हुआ है और क्या यह वास्तव में सुधारा जा सकेगा? सभापति महोदय, जितने भी आर्गनिक कारखाना देखेंगे उत्तर प्रदेश में उनमें से अधिकांश इसलिए मुनाफे में हैं कि उन्हें सरकारी सब्सिडी मिल रही है। यह रासायनिक खाद का जो कारखाना है उसकी उत्पादन लागत भारत में बहुत अधिक है । क्या वजह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में खरे नहीं उतर पाते और हमारी रसायनिक खादें अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की दृष्टि से मूल्य की दृष्टि से बहुत

महंगी हैं। उत्तर प्रदेश की स्थिति तो और भी गई गुजरी है। क्या मंत्री जी इस पर प्रकाश डालेंगे और क्या यह भी बता सकेंगे कि जो टाटा केमिकल के बारे में लिखा है कि उसको 27 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि अखबारों में दो दिन पहले ही था कि उसे भारी घाटा हुआ है और उन्होंने अपने प्रबंध निदेशक तक को सब को इसीलिए बदल दिया। कहां की जानकारी सही है- अखबार की सही है या मंत्री जी की जानकारी सही है?

श्री सुरेश प्रभू: सर, गोरखपुर के बारे में पूछा है कि वहां कितना घाटा हुआ। 1990—2000 तक 187.31 करोड़ का घाटा हुआ है। आपने यह भी जानना चाहा है कि भारत में जो यूरिया बनता है वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्द्धा में क्यों नहीं टिक पा रहा है? सर, फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन करने के लिए सबसे जरूरी स्टॉक जो होता है वह फीड स्टॉक का होता है। हमारे पास जो नेचुरल गैस है उसकी कीमत साढ़े तीन डालर बीटीयू है और यदि फारेन में जाकर उसको देखने की कोशिश करेंगे तो उसकी कीमत 70 सेंट्स कम होती है। यह तो हमारी एक बहुत बड़ी डिस-एडवान्टेज पोजीशन होती है। जब हम किसी कम्पटीशन में जाते हैं तो हमारी जो फीड स्टॉक की प्राइस है वह इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से यदि हम उसमें कम्पटीशन करना चाहें तो फर्टिलाइज़र प्रोडक्शन यूरिया में इंटरनेशनल कम्पटीशन में हम नहीं टिक पाते हैं। जहां से हम इम्पोर्ट करते हैं, एक तो सीआईएस कंट्रीज हैं या गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वे उसके बेस के ऊपर ही फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो ओबीयसली जो उनकी कीमत है, जो दाम हैं वह हमसे कम होंगे। आपने यह जानना चाहा है कि टाटा फर्टिलाइज़र के संबंध में जो मैंने जानकारी दी है वह सही है या कम्पनी ने जानकारी दी है वह सही है। मैं मानता हूं कि दोनों जानकारी सही हैं, क्योंकि मैंने जो जानकारी दी है वह 31 मार्च, 2000 की है और वह जो आपने अखबार में पढ़ा है वह 30 जून, 2000 का है।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': सभापति जी, मंत्री जी ने अपने उत्तर में भी इस बात का संकेत दिया है और जहां तक हमें जानकारी है सिद्धान्त रूप में यह निर्णय ले लिया गया है कि जो गोरखपुर में फर्टिलाइज़र का कारखाना है उसको अब कृभको चलायेगा। जैसा इस प्रश्न के उत्तर की अंतिम पंक्ति में भी मंत्री जी ने कहा है कि सरकार द्वारा उस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। बाद की जानकारी में मंत्री जी ने यह कहा है कि वह बीआईएफआर में चला गया है और वहां से निर्णय होने के बाद स्वामित्व परिवर्तित किया जायेगा। अब यह स्वामित्व परिवर्तन की स्थिति पर आकर के मामला रुक गया है। इसके साथ ही साथ हमारी जानकारी यह है कि और राज्यों में जो

कारखाने हैं उनको प्राथमिकता देने के कारण ही सम्भवत: इसमें विलम्ब हो रहा है। गोरखपुर का कारखाना बहुत दिनों से बंद है और अगर मंत्रिमंडल को ही इस पर निर्णय लेना है तो हम मंत्री जी से यह जानना चाहेंगे कि मंत्रिमंडल इस पर कब तक निर्णय लेगा?

श्री सुरेश प्रभू: सर, इसकी समय-सीमा तो मैं निर्धारित नहीं कर सकता हूं क्योंकि शायद प्रधान मंत्री जी भी कर सकेंगे या नहीं यह मुझे पता नहीं है।....(**व्यवधान**)..

श्री नरेन्द्र मोहन: आप अनुमान तो बता दीजिए?

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': इसको दो महीने में, चार महीने में चलाने की घोषणा तीन प्रधान मंत्री जी वहां जाकर कर चुके हैं। अगर इसके बाद भी इस तरह की स्थिति है तो बड़ी कठिन स्थिति हो जायेगी।

श्री सुरेश प्रभू: सर, समय-सीमा निर्धारित करना तो मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा इसके ऊपर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निर्णय लिया जाए।

श्री नरेन्द्र मोहन : मंत्री जी आप समय-सीमा तो बता दीजिए ।

श्री राजनाथ सिंह 'सूर्य': सर यह मंत्रिमंडल के निर्णय के लिए पड़ा हुआ है।

+मोहम्मद आज़म ख़ान: सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश में फर्टिलाइज़र का एक बड़ा कारखाना गोरखपुर में है और दूसरा आवला में है। तकरीबन दोनों जगह पर घाटे की एक सी ही समस्या है। घाटे का जिक्र तो आ जाता है और जनता को भी पता है कि सरकारी चलने वाले कारखानों में बड़ा घाटा रहता है। लेकिन यह नहीं मालूम होता है कि घाटा किस मद में है? प्रोडक्शन हुआ और जब बिकने के लिए गया तो इन दोनों के बीच का जो घाटा है या तो लोग कारखाने का गलत मैनेजमेंट करते हैं उसकी वजह से घाटा है यानी मजदूर काम नहीं करते, पूरे घंटे काम नहीं करते या अफसरान की गाड़ियों के तेल का खर्च, उनकी एयर कंडीशंनर्स का खर्च, इन सबके कारण घाटा है महोदय, तजुर्बे में यह आया है कि इस तरह के जितने भी कारखानें उत्तर प्रदेश में बंद हैं उनमें इल्ज़ाम तो यह लगाया जाता है कि मजदूरों के काम की चोरी की वजह से कारखाना बंद हो गया, लेकिन जांच की गई तो यह तथ्य सामने हैं कि मैनेजमेंट की फिज़ूलखर्ची के बिनाह पर बड़े-बड़े कारखानों का भट्ठा बैठ गया है। इसलिए मैं इस कारखाने के बारे में यह जानना चाहूंगा, यह मालूम होना चाहिए कि इस कारखाने के घाटे का कारण क्या है? जो खाद बना, उसके बिकने में या न बिकने में या उससे मुनाफे में होने वाला घाटा इसका कारण है या मैनेजमेंट की किसी गलती से, मिस-मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट की इखराजात बहुत ज्यादा होने से इसमें घाटा हुआ

†* Transliteration of the speech in Persian script is available in the Hindi version of the Debate.

है। इसमें बहुत ज्यादा अफसरान रख लिए हैं, ज्यादा गाड़ियां हैं, ज्यादा कोठियां हैं, ज्यादा मेंटीनेंस हैं, जो काम एक अफसरान के रहने से चल सकता है वहां दस-दस, बीस-बीस अफसरान हैं, देखने में यह आया है कि पूरे कारखाने का खर्च एक तरफ है और दूसरी तरफ पूरी मैनेजमेंट का खर्च है जिसमें खासतौर से उच्च श्रेणी के अफसरान हैं। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि घाटे की असल मद क्या है?

श्री सुरेश प्रभू: सर, माननीय सदस्य ने घाटे के अलग-अलग पहलू तो बता दिए हैं, शायद इन सबको मिलाकर ही घाटा बना होगा। यह जो गोरखपुर का प्लांट है यह 1969 में कमीशंड किया गया और जो इंजीनियरिंग कारपोरेशन, जापान ने टेक्नोलोजी वहां लगाई है, जो टेक्रालॉजी वहां पर काम कर रही है, इसमें टेकनीकल डिफेक्ट पाए गए हैं।

इसलिए मित्सुई टोट्सो प्रोसैस को लेकर उसको दुबारा शुरू करने की कोशिश की गयी। उसकी डिज़ाईन ओरिजनल कैपेसिटी 1.74 लाख मीट्रिक टन थी, उसको 2.85 लाख मीट्रिक टन वायबिलिटी लाने के लिए किया गया। उसमें पॉवर की भी प्रॉब्लम थी। यह सब होने के बाद 10 जून 1990 से यह कारखाना बंद है। इसके बाद जो लॉस हुआ है, वह मैं मानता हूं कि स्टैडिंग चार्जिज़ की वजह से हुआ है लेकिन यह जनरल बातें जो आपने कहीं..

श्री मोहम्मद आज़म ख़ान: असली कारण वही है जो आप नहीं कहना चाह रहे हैं।

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The Minister has said that in 1980-90 there was a fire accident iiLthis unit. A decade has passed. To put the record straight I would say that the Government could not take decision after that fire accident. That unit was declared unsafe and, for ten years, they could not take a decision whether they have to replace the equipment to restart the plant or to modernise it. It is very unfortunate if the blame is put on the workers for the present state of affairs. Right now, as the Minister has said, one thing is very clear; the Gorakhpur unit of the F.C.I, has to be closed down and the workers have to out of job. Then only the KRIBHCO will start construction. An impression is being given that this project is being taken over and then a new unit will start. If I am not mistaken, will the hon. Minister assure that it means, all the workers working in the Goraphpur unit will not be out of job if the unit is closed down and KRIBHCO takes it over. My point is, what will happen to the workers?

SHRI SURESH PRABHU: Sir, as the hon. Member himself has said this plant has not functioning since 10th June, 1990. We are acting on a proposal wliicji has been received from a third company, KRIBHCO. The proposal contains certain conditions, which have

been mentioned. But, to the extent possible we will prevail upon KRIBHCO to make sure that they take all of them. But if you put the condition that you have to taken them completely, then nothing will happen. These are conditionalities, which have been approved, in consultation with the State Government, from time to time and **this** is the agreement that has been reached. However, I would definitely try to prevail upon KRIBHCO to ensure that, to the extent possible, they take the people who are already working there.

श्री सूर्यभान पाटील वहाडणे: महोदय, मैं केवल एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। 1990 में यह प्रोजैक्ट बंद हुआ। इसमें बाद में ही रूचि दिखायी गयी। बाद में ही सिद्धांततया स्वीकार किया और बाद में ही अनुमोदनार्थ भेजा गया। मैं इस संबंध में केवल यही प्रश्न करना चाहता हूं कि क्या 2010 के पहले यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा?

श्री सुरेश प्रभू: सर, मैं इतना पैसीमिस्ट नहीं हूं। लेकिन इतना ऑप्टीमिस्ट भी नहीं हूं कि कुछ महीने में कहूं।

Discrimination between Allopathic and Indian Systems of Medicine

***183.** SHRI ABANI ROY: Will the Minister of HEALTH **AND** FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether the facilities extended to CGHS doctors in Allopathic system are also given to CGHS doctors of Indian Systems of Medicine;

(b) if not, the reasons for the discrimination;

(c) whether the number of CGHS dispensaries/units of allopathic system set up during the past few years in the capital also do not compare with the CGHS dispensaries/units of ISM; and

(d) if so, the reasons for the discrimination?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C.P. THAKUR): (a) to (d) A statment is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.
(b) In view of (a) above, the question does not arise.